विमान वाहक पोत विक्रांत का जनक है कोच्चि शिपयार्ड

कहते हैं कि जिस देश ने अपनी समुद्री सीमा की मजबूत किलेबंदी कर दी और उसे अभेद्य बना दिया तो फिर उस देश की सामरिक शक्ति दुनिया के किसी भी बड़े देश को मजबूत चुनौती पेश कर सकता है. ऐसे समय जब कि दुनिया एक अलग तरह के वार गेम में फंसा हुआ है, तब तो उस देश की नौ सेना की ताकत का महत्व और बढ़ जाता है. कमोबेश यही स्थिति भारत के लिए भी है. भारत की गिनती दुनिया के चुनिंदा ताकतवर नौ सेना में होती है और यदि इस श्रेय को हासिल करने में कोई शिपयार्ड बड़ा योगदान दे रहा है तो वह कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है.

अरब सागर की लहरों से अठखेलियां खेलता ये शिपयार्ड भारत की गौरव का पथ प्रदर्शक है, जिसने वह क्षमता भी हासिल कर ली है जो कि दुनिया के विशाल विमान वाहक पोत बना सके. कोच्चि शिपयार्ड के विशाल परिसर में ही विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत का निर्माण हुआ है. लगभग 300 मीटर लंबे इस विमान वाहक पोत ने भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को नई ताकत दी है. इस विमान में 70 से अधिक फाइटर जेट खड़े हो सकते हैं. शिपयार्ड के इतिहास में ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है. ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी, जब हमें शिपयार्ड के विशाल परिसर का दौरा करने का सौभाग्य मिला. 1972 में पहले जहाज की आपूर्ति करने से लेकर अब तक शिपयार्ड ने उपलब्धियों का नया मुकाम हासिल किया है. इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के पास अभी 21100 करोड़ रुपए के आर्डर सुरक्षित हैं. इनमें रक्षा क्षेत्र में 14 जहाजों की आपूर्ति भी शामिल है, जिसका मूल्य 13700 करोड़ रुपए है. इसी तरह व्यवसायिक घरेलु जहाजों के 34 आर्डर शिपयार्ड के पास हैं, जिसका मूल्य 1700 करोड़ रुपए है, इसी तरह विदेशों से भी 4200 करोड़ रुपए मूल्य के 27 व्यवसायिक जहाजों के आर्डर शिपयार्ड के पास हैं. इसके अलावा शिप रिपेयर के भी 1500 करोड़ का काम शिपयार्ड को मिला हुआ है. इतना ही नहीं लगभग 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपए के आर्डर अभी अलग- अलग प्रक्रियाओं में है. इनमें रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 20 हजार करोड़ तो व्यवसायिक जहाजों के लिए 65 हजार करोड के आर्डर पाइपलाइन में है. इसी शिपयार्ड को देश के पहले हाईड्रोजन चलित जहाज की आपूर्ति का श्रेय जाता है. सीएसएल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक उनके पास विक्रांत जैसे बड़े और ताकतवर विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है, लेकिन अभी उन्हें भारत सरकार से किसी और विमान वाहक पोत के आर्डर नहीं मिले हैं. यह सब देश की रक्षा जरुरतों के हिसाब से तय होता है. भारत के पास इस समय दो विमान वाहक पोत हैं. दक्षिण एशिया में किसी के पास इस तरह का पोत नहीं है. यदि जरुरत पड़ी और उन्हें मौका मिला तो कम समय में ताकतवर विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता सीएसएल के पास है.

तट की ताकत का उपयोग- करीब 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और वैश्विक व्यापार मार्गों के बीच स्थित होने के कारण भारत के पास समुद्री अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है. इसी ताकत को 'सागरमाला प्रोग्राम' और 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' जैसे बड़े अभियानों के जरिए रणनीतिक रूप से विकसित किया जा रहा है.

सागरमाला के तहत 800 से अधिक परियोजनाएं—जिनमें आधुनिक बंदरगाह, औद्योगिक क्लस्टर और तटीय कनेक्टिविटी कॉरिडोर शामिल हैं—भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रही हैं. वहीं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य भारत को दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री देशों में शामिल करना है, जहां विश्वस्तरीय बंदरगाह, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण व मरम्मत व्यवस्था हो. इस परिवर्तन के केंद्र में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी संस्थाएं हैं, जो दिखाती हैं कि नीतियां कैसे वास्तविक प्रगति में बदलती हैं. भारत के सबसे बड़े जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र के रूप में सीएसएल लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके.

बजट का बड़ा प्रोत्साहन- केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री क्षेत्र को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया गया है. जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और तटीय ढांचे के विकास के लिए सरकार ने कई नई पहलें शुरू की हैं. हाल ही में 69,000 करोड़ रुपये की चार-स्तंभ वाली 'मैरीटाइम डेवलपमेंट इनिशिएटिव' को मंजूरी मिली है, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, ग्रीन शिपिंग और कौशल विकास को आगे बढ़ाना है.

कोचीन शिपयार्ड भी इस राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप अपने विस्तार पर काम कर रहा है. करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से 310 मीटर लंबा नया ड्राई डॉक और अत्याधुनिक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोच्चि में तैयार की जा रही है. इससे भारत की क्षमता बढ़ेगी कि वह अगली पीढ़ी के कैरियर, रुह्त्र जहाज और बड़े वाणिज्यिक पोत बना और उनकी मरम्मत कर सके—ऐसी सुविधाएं अब तक दुनिया के कुछ ही देशों में उपलब्ध थीं.

विकास का नया इंजन- आज समुद्री क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को प्रभावित करता है—व्यापार, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा और रक्षा तक. बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और नए शिप रिपेयर हब के बनने से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार मजबूत हो रही है. इसके साथ ही यह क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है, सहायक उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है और विशेष कौशल कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी के समुद्री पेशेवर तैयार कर रहा है. जो क्षेत्र कभी नीति चर्चाओं के किनारे था, आज वही भारत की विकास गाथा के केंद्र में आ गया है.

हरित समुद्री भविष्य- यदि भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा का पैमाना बड़ा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. ग्रीन शिपिंग अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति बन चुकी है. बंदरगाहों और जहाजों को डीकार्बोनाइज करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं. कोचीन शिपयार्ड इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान के साझेदारों के साथ मिलकर यह शून्य-उत्सर्जन जहाज, हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी और इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाओं का विकास कर रहा है. ये परियोजनाएं भारत को वैश्विक समुद्री समुदाय में एक जिम्मेदार और भविष्य उन्मुख राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही हैं.

कोच्चि से लौटकर कन्हैया लोधी

चिप से शिप' तक भारत की समुद्री छलांग

बहुत पहले, जब भारत ने अंतरिक्ष में पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था, तब वह हवाओं और ज्वार-भाटों को पढ़ना सीख चुका था. लोथल के प्राचीन बंदरगाहों से लेकर कोच्चि के आधुनिक शिपयार्ड तक, समुद्र ने हमेशा भारत को नई संभावनाओं का संदेश दिया है. आज वही संभावनाएं एक बड़े उद्देश्य में बदल रही हैं. भारत एक समुद्री पुनर्जागरण की कहानी लिख रहा है, जो देश की अगली बड़ी आर्थिक छलांग साबित हो सकती है. पिछले एक दशक में भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, ग्रीन पोर्ट्स और तटीय लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है. लक्ष्य साफ है—2047 तक, यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक, भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना. यह महत्वाकांक्षा 'अमृत काल' के उस विजन से भी जुड़ी है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना शामिल है. हाल ही में गुजरात में समुद्र से समृद्धि पहल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की मंशा दोहराई कि देश अब चिप से शिप तक हर चीज का निर्माण करेगा. उनके इस बयान ने उस गति को और स्पष्ट कर दिया, जो पिछले कुछ वर्षों में नीतिगत सुधारों, बड़े निवेश और मजबूत इरादों के जरिए तैयार हुई है.

भविष्य की ओर बढ़ता भारत

'चिप से शिप' तक का भारत का सफर केवल औद्योगिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक घोषणा है कि देश की आर्थिक प्रगति अब उसके समुद्रों से भी शक्ति लेगी. इंजीनियरों की क्षमता, तकनीक का नवाचार और आत्मनिर्भरता का विश्वास—इन्हीं के सहारे भारत वैश्विक समुद्री नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है. जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य स्पष्ट है—दुनिया की शीर्ष पांच समुद्री शक्तियों में जगह बनाना. इस यात्रा में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि उस नए भारत का प्रतीक बन चुका है, जो अपने समुद्री सामर्थ्य के साथ वैश्विक मंच पर आगे बढने के लिए तैयार है.

इच्छामृत्यु : एक अधिकार गरिमापूर्ण मृत्यु का

हरीश राणा के इच्छामृत्यु के सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर फिर एक बार, जीवन के अंत करने के अधिकार को लेकर कानून की आवश्यकता नज़र आने लगी है. कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के सदस्य सालों से कोमा में हैं या किसी ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि इलाज करवाने के लिए उनके पास न तो संसाधन हैं और न ही उन्हें कहीं से मदद मिल पा रही है. तब ऐसे में दुर्गति उस मरीज़ की हो रही है. इसी तरह का केस हरीश राणा का भी था और उनके माता-पिता द्वारा ही सरकार से अपील की गई कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए.

तृप्ति मिश्रा

क्या हुआ था हरीश राणा को- सन् 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ से बी टेक के छात्र थे और अपने पीजी से चौथी मंज़िल से गिर गये थे. सिर पर लगी गंभीर चोटों की वजह से वह आज तक कोमा में हैं. डॉक्टरी भाषा में उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया हुआ है जिसमें, पिछले 13 वर्षों से वह कुछ महसूस नहीं कर सकते और वेंटिलेटर के माध्यम से साँस लेते हैं.

देश में अपनी तरह का पहला मामला- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने यह फैसला दिया जिसमें हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया के माध्यम से इच्छा मृत्यु दी जाएगी. देश में इच्छा मृत्यु का अपनी तरह का यह प्रथम मामला है.

भारत का यूथेनेशिया कानून

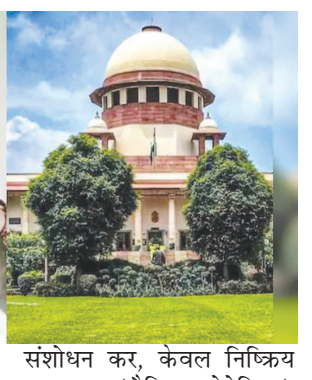

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत 'गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार' को मान्यता दी गई है. 2018 में कॉमन कॉज नामक संस्था द्वारा लगाई गई याचिका पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया और 2023 में संशोधन कर, केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) और 'लिविंग विल' वैध करार दिया गया. जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु (एक्टिव यूथेनेशिया) प्रतिबंधित है. लिविंग विल में अगर कोई व्यक्ति अपने जीते जी कोई वसीयत बना जाए कि किसी विशेष परिस्थिति में उसे यूथिनाइज किया जा सकता है तब उसे किसी गंभीर बीमारी में इच्छामृत्यु प्रदान की जा सकती है. वहीं एक्टिव यूथेनेशिया में इन्जेक्शन या कोई दवाई से मरीज़ को मृत्यु दी जाती है जबकि पैसिव यूथेनेशिया में किसी लाइलाज बीमारी में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अगर उस मरीज़ के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती एवं उसके करीबी रिश्तेदारों की सहमति से उसके लाइफ़ सपोर्टिंग इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, भोजन ट्यूब आदि निकाल दिया जाता है. ताकि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हों सके.

हरीश के मामले में यही किया गया. हरीश के माता पिता द्वारा ही यह गुहार लगाई गई थी कि पीछे तेरह वर्षों से उनके बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि बिस्तर पर रहने से कई घाव हो गए हैं. हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है जिससे उसकी देखभाल करना मुश्किल हो गया है. डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार भी हरीश के ठीक होने के कोई आसार नहीं थे.

कानून कितना आवश्यक

हमारे देश में इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है. पर बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन, कुछ मामलों में जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उरुग्वे आदि देशों में यह अलग अलग रूप में मान्य है. गंभीर चिकित्सकीय मामलों में डॉक्टरी अनुमति के साथ इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई है. देश में ऐसे अनेक केस हैं. हरीश राणा के लिए आए इस निर्णय ने उन परिवारों के लिए एक दरवाज़ा खोला है जिनके परिजन किसी अपने को शांति से मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में सरकार को कानून बनाने के लिए निर्देशित भी किया है.

बदल गई नेपाल की राजनीति

डॉ .ब्रह्मदीप अलूने
(अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार)

अभिजात्य और कुछ विशिष्ट राजनीतिक दलों तथा उसके सत्तावादी नेताओं से अभिशिप्त रही नेपाल की राजनीति में बालेन शाह के उभार को एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. नया नेतृत्व देश की आंतरिक राजनीति, व्यवस्थाओं और पड़ोसी देशो से संबंधों को लेकर ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट नजर आ रहा है,इससे नेपाल के भविष्य की नई उम्मीदें जागी है. बालेन शाह तकनीकी विकास से रोजगार पैदा करके देश को गढ़ना चाहते है तथा कर्ज के बोझ तले दबी विकास परियोजनाओं को लेकर वे सहज नहीं है,इसलिए भारत में भी इस परिवर्तन को आशा की दृष्टि से देखा जा रहा है. इसका कारण यह है कि नेपाल में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था 2008 में खत्म होने के बाद प्रचंड पहली बार जब 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने पहला विदेशी दौरा चीन का किया था . वहीं 2008 से अब तक किसी भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार नहीं बनाई.

लोकतांत्रिक नेपाल की शुरुआत से लेकर जेन जी आंदोलन तक कम्युनिष्ट पार्टी से प्रभावित नेपाल की राजनीति अस्थिरता के साथ चीन से प्रभावित रही. अब बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल में नई समावेशी,स्थिर और संतुलित सरकार भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध,खुली सीमा,गहरे सांस्कृतिक संबंध,ऊर्जा तथा व्यापार के क्षेत्र में संभावित सहयोग दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं. वहीं चीन की नीतियां नेपाल के नए नेतृत्व को आशंकित करने वाली है. जाहिर है यदि बालेन शाह दूरदर्शितापूर्ण और संतुलित विदेश नीति के मार्ग पर आगे बढ़ते है तो इससे भारत-नेपाल संबंधों में पहले जैसी ताजगी और गर्माहट आएगी.

पिछले डेढ़ दशक से ज्यादा समय से नेपाल की समस्या राजनीतिक अस्थिरता रही है. पिछले कई वर्षों में सरकारें बार-बार बदलती रही है,जिससे सामाजिक और आर्थिक नीतियों में निरंतरता नहीं बन पाई. इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ा है. देश में गरीबी तेजी से बड़ी है,उद्योग-धंधे सीमित है,रोजगार के अवसर बेहद कम हैं और बड़ी संख्या में युवा विदेशों में काम करने के लिए मजबूर हैं. देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी रोजगार से आने वाले पैसे पर निर्भर है. नेपाल में प्रशासनिक व्यवस्था बेहद लचर है और भ्रष्टाचार से आन जनता बेहाल है. सरकारी योजनाएं अक्सर सही ढंग से लागू नहीं हो पाती,जिससे जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता. इसके अलावा आधारभूत ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती है. सड़क,स्वास्थ्य,शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बहुत सुधार की आवश्यकता है. हिमालय की तलहटी और पहाड़ों में बसा यह देश प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित रहा है.

पिछले वर्ष नेपाल में जेन-जी आंदोलन मुख्य रूप से नई पीढ़ी की निराशा, बेरोज़गारी और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष का प्रतीक बनकर उभरा. युवा देश में बदलाव चाहते है और उनकी सबसे बड़ी मांग जवाबदेह राजनीति की रही. युवाओं का कहना था कि पारंपरिक राजनीतिक दल वर्षों से सत्ता में रहते हुए भी देश को स्थिर विकास नहीं दे पाए हैं. इसलिए वे पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई चाहते है. नेपाल के लाखों युवा रोज़गार के लिए विदेश जाने को मजबूर हैं. आंदोलन में युवाओं ने मांग थी कि सरकार देश के भीतर ही उद्योग,पर्यटन और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएं. आंदोलन के दौरान डिजिटल पारदर्शिता,सुशासन और युवा नेतृत्व को राजनीति में अवसर देने की मांग भी जोर से उठी थी. आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना था कि देश की नीतियों और निर्णयों में नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़नी चाहिए. जेन-जी आंदोलन से यह संदेश मिला कि नेपाल के युवा अब केवल राजनीतिक बदलाव नहीं,बल्कि ईमानदार शासन,आर्थिक अवसर और देश में आधुनिक विकास मॉडल चाहते हैं.

इन समस्याओं के बीच नई सरकार से लोगों की उम्मीदें काफी बड़ी हैं. बालेन शाह नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद और के प्रतीक बनकर उभरे हैं. काठमांडू के मेयर बनने के बाद उन्होंने प्रशासन चलाने का ऐसा तरीका अपनाया है,जो पारंपरिक राजनीतिक शैली से काफी अलग दिखाई देता है. वे तुरंत निर्णय लेने,अनुशासित व्यवस्था,नियमों को सख्ती से लागू करने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देते है. बालेन शाह की कार्यशैली को व्यावहारिक और परिणाम-केंद्रित माना जाता है. उन्होंने काठमांडू में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई,शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था सुधारने जैसे मुद्दों पर सक्रिय कदम उठाएं. उनकी एक विशेषता यह भी है कि वे आम लोगों से सीधे संवाद बनाए रखते हैं और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी योजनाओं और निर्णयों की जानकारी साझा करते हैं. इससे युवाओं को लगता है कि शासन अधिक खुला और जवाबदेह बन सकता है. नेपाल के युवाओं को उनसे कई बहुत उम्मीदें हैं. वे ओली की भारत विरोधी तथा प्रचंड की चीन परस्त राजनीति से अलग चाहते हैं कि बालेन शाह गैर विवादित रहकर ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन की एक नई परंपरा स्थापित करें. युवाओं का यह भी मानना है कि बालेन शाह तकनीकी समझ और आधुनिक सोच के साथ वे शहरी विकास, रोजगार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में ठोस बदलाव ला सकते हैं. नेपाल की नई पीढ़ी बालेन शाह को एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देख रही है जो पुरानी राजनीतिक संस्कृति से हटकर साफ-सुथरी राजनीति,प्रभावी प्रशासन और विकासोन्मुख सोच को आगे बढ़ा सकता है.

नेपाल के विकास,व्यापार,ऊर्जा और सामाजिक संबंधों के विस्तार में भारत की भूमिका अहम है. नेपाल के विकास और स्थिरता में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. नेपाल की बड़ी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियां भारत के साथ होती हैं. नेपाल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य उपभोक्ता सामान का बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है. नेपाल के आधारभूत ढांचे के विकास में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है.

नेपाल में जलविद्युत की अपार संभावनाएं है और इन परियोजनाओं के विकास में भारत निवेश और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है. कई सड़क,पुल और रेल परियोजनाओं में भी भारत की सहायता से काम आगे बढ़ रहा है. सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी दोनों देशों को करीब लाते हैं. दोनों देशों के लोगों के बीच धार्मिक और पारिवारिक रिश्ते लंबे समय से बने हुए हैं. लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं,जिससे दोनों देशों के बीच मानवीय संबंध और मजबूत होते है.

व्यंग्य

विधानमंडलों में मिस्टर इंडिया...

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

विधानमंडलों की खाली कुर्सियां देख कर 1987 में एक हिंदी साइंस फिक्शन फिल्म आई थी, नाम था 'मिस्टर इंडिया'. इस फिल्म में नायक अनिल कपूर ने मिस्टर इंडिया की भूमिका अदा की है. मिस्टर इंडिया की कलाई पर एक घड़ी नुमा यंत्र बंधा होता है. जिसका बटन दबाने पर इसको पहनने वाला व्यक्ति अदृश्य हो जाते हैं और पुनः बटन दबाने पर फिर से साक्षात् प्रकट हो जाता है .

हमारे विधान मंडलों भी एक लंबे समय से यही दृश्य देखने में आ रहा है. यहां भी सदस्य अपनी मर्जी के अनुसार प्रकट होते हैं और अदृश्य हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल विपक्ष के दलों में ही है. यही स्थिति सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में भी है. लंच के पहले तो फिर भी सदस्यों की मौजूदगी तो फिर भी सम्मान जनक कही जाती है. परंतु लंच के बाद खाली खाली सीटें सदनों का मुंह चिढ़ाने जैसी लगतीं हैं.

ऐसा लगता है कि हमारे प्रजातंत्र के चुने हुए कर्णधारों को मिस्टर इंडिया वाला वह यंत्र या फॉर्मूला हत्थे लग गया है.जिसका उपयोग वे विधान मंडलों से गायब रहने में धड़ाधड़ कर रहे हैं. उनकी जब मर्जी होती है वह सदन में उदयमान हो जाते हैं और जब मर्जी होती है धड़धड़ा कर निकल जाते हैं. फिर विधान मंडलों की उपस्थिति पंजी सबूत पेश करती है कि वे सदन में मौजूद रहे थे. जहां वे बैठते हैं वहां आना उनके लिए जिम्मेदारी कम एक औपचारिकता भर सी महसूस होती है.

सत्र के दौरान यह माननीय जितनी संख्या में सदन में होते हैं उससे ज्यादा उनकी संख्या कैंटीनों में या लॉबी में मिल जाती है . कैंटीन में या फिर वे दिल्ली दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं.कहा यह जाता है कि जिसे सरकारी खजाने से वेतन मिलता है वह पब्लिक सर्वेंट होता है और वह कुछ नियमों और कानूनों से बंधे होते हैं. परंतु कानून बनाने वाले इन नियमों की खिल्ली उड़ाते नज़र आते हैं. कानून बनाने वाले स्वयं भू रूप से इन सब बंधनों और जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं. इन पर संत मलूक दास द्वारा कही यह बात सोलह आने सटीक बैठती है.अजगर करे न चाकरी,पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम.बस एक बार का इनवेस्टमेंट फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट.

सरकारी नौकर को तनख़ाह ऐसे ही नहीं मिल जाती है.सत्रह बंधन, सत्रह बंदिशें, सत्रह मालिक. द्वार द्वार पर बंदगी और दूसरी तरफ न कोई नौकरी न चाकरी,न तबादला, न सस्पेंशन. यदि कुछ है तो वह है हेकड़ी और स्वयं के राजा होने का भाव. देश दुनिया में फ्री फोकट में हवाई जहाज और रेल के ऊंचे दर्जे में यात्रा.लाखों की सेलरी,कमीशन अलग से, ऊपर से जय जयकार. न कोई झंझट न कोई रिस्पांसबिलिटी,और दल बदल के लिए करोड़ों के ऑफर अलग से. इसके बाद भी दूध के धुले के धुले . गंगा की तरह पवित्र. पांच साल के ऐश के बाद जीवन भर मुफ्त पेंशन अलग से. इसे कहते हैं सोने की कलम से किस्मत लिखा होना.

कहां सांसद और विधायक जी कहां सरकारी बाबू. कोई मेल है. समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक. वहां आते अंगूठा जाते अंगूठा गज़ब तमाशा अंगूठा. प्रजातंत्र में आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण अंगूठा हो गया. जब देश अनपढ़ था तब भी अंगूठा इंपोर्टेंट था. आज देश में 81 प्रतिशत होने के बाद भी अंगूठा महत्वपूर्ण बना हुआ है. अंगूठा ऑल द बेस्ट का भी संकेत है. तो दूसरी तरफ विधायक या सांसद बनने के बाद अंगूठा मतदाताओं को दिखाए जाने वाला तोहफा होता है. वर्तमान स्थिति में यह गाना याद आता है मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं मर्जी. बेचारी इस मेरी मर्जी का शिकार बनी हुई है.